राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ग्याहरवां दीक्षांत समारोह

कृषि अर्थशास्त्र की स्मार्ट विधा को विकसित करें विश्वविद्यालय – राज्यपाल

जयपुर, 22 दिसम्बर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने कहा है कि कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों से खेती में क्रान्ति आई है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। उन्नत बीजों व अद्यतन तकनीक से किसानों को खेती की भरपूर उपज मिल रही है, परन्तु मेरा मानना है कि कृषि विश्वविद्यालयों व वैज्ञानिकों को पैदावार बढ़ाने तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि बढ़ी हुई पैदावार का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक उस पैदावार का लाभकारी मूल्य किसानों को ना मिले। श्री सिंह का मानना था कि उद्योगों की ही भाँति कृषि को भी बाजार के अर्थशास्त्र से जोड़ने का काम करना होगा। इसके लिए कृषि अर्थशास्त्र की स्मार्ट विधा को विश्वविद्यालयों को विकसित करना होगा।

राज्यपाल श्री सिंह शुक्रवार को उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ग्याहरवें दीक्षांत समारोह को सम्बोन्धित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि आज देश के विभिन्न भागों से आए दिन यह समाचार मिलते रहते हैं कि अमुक फसल के औने–पौने दाम मिल रहे हैं। आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ रहे हैं, गन्ने को खेतों में जलाया जा रहा है, टमाटर घर पर रखने की बजाय सड़कों पर फेंक देना ज्यादा लाभ का सौदा बन रहा है आदि–आदि। यह स्थितियाँ क्यों आ रही है? इसका क्या समाधान है? इन पर भी कृषि विश्वविद्यालयों को अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा।

श्री सिंह ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को सरकार से सामंजस्य बनाते हुए बाजार की दिशा एवं उपभोक्ता डिमाण्ड का भी अध्ययन करना चाहिए। उन्हें यह आंकलन करना चाहिए, डाटा तैयार करना चाहिए कि कौनसी फसल कितनी मात्रा में बोने पर डिमाण्ड व सप्लाई का सामंजस्य बना रहेगा। विश्वविद्यालयों को किसानों, उपभोक्ताओं और बाजार के बीच संतुलन स्थापित करने की भूमिका भी निभानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि दुनिया के कई ऐसे देश है, जहाँ भविष्य की मांग का आंकलन कर तद्नुसार किसानों को कितने क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, इस आशय की एडवाईजरी जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों को इस दिशा में और इस दायित्व को उठाने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए। बिना मांग का आंकलन किये फसलों का उत्पादन, जहां किसान को उपज का सही मूल्य नहीं मिलने देता, वहीं उपज की बर्बादी से राष्ट्रीय क्षति भी होती है।

———

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
जनसम्पर्क अधिकारी, राज्यपाल